

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

**माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एस. जे. वज़ीफदार और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल के समक्ष**

डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ-2015 का प्रतिवादी सी. डब्ल्यू. पी. No.25356

23 फरवरी, 2017

**ए. मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. 2-परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों का वर्गीकरण-विशुद्ध रूप से निजी उपयोग और वाहनों के वाणिज्यिक उपयोग के बीच एक बोधगम्य अंतर है-वाहनों के विशुद्ध रूप से निजी उपयोग और व्यापार और व्यवसाय के संबंध में व्यक्तियों को ले जाने के लिए वाहनों के उपयोग के बीच भी बोधगम्य अंतर है-यह खंड 2 (33) के तहत परिभाषित निजी सेवा वाहन की श्रेणी में आएगा और इसे आगे परिवहन वाहन कहा जाएगा।**

माना जाता है कि विशुद्ध रूप से निजी उपयोग और वाहनों के वाणिज्यिक उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इसी तरह वाहन के विशुद्ध रूप से निजी उपयोग और व्यापार या व्यवसाय के संबंध में व्यक्तियों को ले जाने के लिए वाहनों के उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

(पैरा 8) ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के वाहन जो व्यापार और व्यवसाय के संबंध में कर्मचारियों को ले जा रहे हैं, वे उप-खंड 2 (33) में परिभाषित निजी सेवा वाहन की श्रेणी में आते हैं। एक बार जब याचिकाकर्ताओं के वाहन निजी सेवा वाहन की श्रेणी में आते हैं, तो यह स्वयंसिद्ध है कि यह परिवहन वाहन की श्रेणी में आएगा।

(पैरा 9)

**बी. पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952-अपने कर्मचारियों को ले जाने वाले याचिकाकर्ता के वाहनों को अधिनियम के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा में शामिल किया गया है-इसके कर्मचारियों सहित यात्रियों को अधिनियम के तहत यात्री कहा जाता है और केवल चालक, कंडक्टर और क्लीनर को बाहर रखा जाता है-केवल इसलिए कि कंपनी अपने कर्मचारियों से शुल्क नहीं लेती है इसका मतलब यह नहीं है कि किराया की गणना नहीं की जा सकती है-यात्रियों पर किराया लगाया जा सकता है; और कंपनी के कर्मचारी यात्री हैं।**

डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार और ए. एन. ओ. टी. आर. बनाम भारत का संघ और

अन्य (जे. अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के वाहन जो अपने कर्मचारियों को ले जा रहे हैं, उन्हें पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 में परिभाषित मोटर वाहन की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

(पैरा 12) ने आगे कहा कि जिन कर्मचारियों को उनके आवास से मिल तक ले जाया जा रहा है, उन यात्रियों को यात्रियों की परिभाषा के दायरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। परिभाषा में केवल वाहन के संबंध में कर्तव्यों के निर्वहन में चालक, कंडक्टर या एक कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया है जो अच्छी तरह से स्वच्छ हो सकता है आदि लेकिन कंपनी के अधिकारी जिनका वाहन से कोई संबंध नहीं है।

(पैरा 13) ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी अपने कर्मचारियों से शुल्क नहीं लेती है, इसका मतलब यह नहीं है कि किराया की गणना नहीं की जा सकती है। इसकी गणना खंड 3 (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार की जानी चाहिए। निजी वाहक के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों पर किराया लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कर्मचारी यात्री हैं। याचिकाकर्ता कंपनी के वाहन मोटर वाहन हैं न कि निजी वाहक जो सामान आदि ले जाते हैं। इसलिए, वे पूरी तरह से खंड 2 (i) में आते हैं।

(पैरा 15)

विनोद एस. भारद्वाज, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

आलोक जैन, भारत संघ के अधिवक्ता

ममता सिंगला तलवार, डी. ए. जी, हरियाणा।

**अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल, जे।**

(1) याचिकाकर्ता कंपनी ने अपने वाहनों को निजी सेवा वाहन मानने के बाद उन्हें गैर-परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की है। इसने राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने के लिए निर्देश जारी किए जाने तक 14.09.2004 दिनांकित ज्ञापन को अलग करने का भी अनुरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में प्रविष्टि संख्या (x) को इस हद तक अलग रखने के लिए कि किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत केवल निजी सेवा वाहनों को गैर-परिवहन वाहन के रूप में परमादेश जाए और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को बिना कोई यात्री कर लिए वाहन के सरशियोरेराई नवीनीकृत करने और पहले से भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए एक अनिवार्यता भी मांगी गई है।

2017(1)

(2) डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार के नाम से पंजीकृत याचिकाकर्ता कंपनी ने तीन वाहन यानी दो महिंद्रा बोलेरोस और एक आयशर 10.90 एल. खरीदे हैं। इन वाहनों का उपयोग कर्मचारियों को उनके आवास से याचिकाकर्ता की कपड़ा मिल में लाने के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ता का मामला है कि इन वाहनों का उपयोग किसी भी किराए या इनाम या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है और इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 2 (33) के तहत निजी सेवा वाहन की परिभाषा के तहत शामिल हैं।

(3) दिनांक 1 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है कि केवल व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को गैर-परिवहन वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाए, जबकि एक कंपनी के स्वामित्व वाले वाहनों को परिवहन वाहन माना जाता है और यात्री कर के अधीन किया जाता है। याचिकाकर्ता कंपनी ने पहले 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.1871 को प्राथमिकता दी थी, जिसमें कुछ इसी तरह की राहत का दावा किया गया था, जैसा कि तत्काल याचिका में दावा किया गया था, जिसे इस अदालत की एक खण्ड पीठ द्वारा 07.09.2015 पर प्रतिवादी को याचिकाकर्ता कंपनी के प्रतिनिधित्व पर एक बोलने का आदेश पारित करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पारित दिनांकित 04.11.2015 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसे इस याचिका में भी आक्षेप किया गया है।

(4) याचिकाकर्ता कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि केवल व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत और किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले वाहनों को गैर-परिवहन वाहन मानते हुए निजी सेवा वाहन का गैर-परिवहन और परिवहन वाहन के रूप में वर्गीकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि अधिनियम केवल मालिक के नाम पर वाहनों के पंजीकरण को संदर्भित करता है और किसी व्यक्ति या कंपनी सहित किसी भी न्यायिक व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं करता है। 'स्वामी' शब्द में व्यक्ति और कंपनी दोनों शामिल हैं और इन्हें आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि कंपनी द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से मिल तक ले जाने के उद्देश्य से हैं। कर्मचारियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। वाहनों का उपयोग विशेष रूप से कंपनी द्वारा अपने कुशल कामकाज के लिए किया जाता है न कि किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए और इसलिए, इसे किसी भी तरह के वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, ताकि इसे गैर-परिवहन वाहन के वर्गीकरण से अलग किया जा सके जैसा कि एक व्यक्तिगत मालिक के मामले में है और दिनांकित 05.11.2004 अधिसूचना में ऐसा वर्गीकरण मनमाना और भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार इसे रद्द किया जा सकता है।

(5) इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार और एक अन्य बनाम भारत का संघ और

अन्य (जे. अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल)

उन्होंने तर्क दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम की योजना में वाहनों को सार्वजनिक और निजी सेवा वाहनों के साथ-साथ परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रूप में वर्गीकृत करने का प्रावधान है। पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, हरियाणा राज्य तक विस्तारित राज्य सरकार को परिवहन वाहनों पर यात्री कर लगाने का अधिकार देता है और इसलिए, इस संबंध में प्रतिवादी की कार्रवाई को दोष नहीं दिया जा सकता है।

(6) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 2 के प्रासंगिक प्रावधानों और अधिसूचना दिनांक 05.11.2004 का उल्लेख करना आवश्यक है जो इसके बाद दिए गए हैं:-

“ खंड 2-(21) "हल्का मोटर वाहन" से एक परिवहन वाहन या सर्वव्यापी वाहन जिसका सकल वाहन वजन दोनों में से किसी एक का है या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर जिसका भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है; (21 ए) "निर्माता" से एक व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर वाहनों के निर्माण में लगा हुआ है;

(22) “मैक्सिकैब "से कोई भी मोटर वाहन अभिप्रेत है जो किराए या पुरस्कार के लिए छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया है, लेकिन चालक को छोड़कर बारह से अधिक यात्रियों को नहीं, (23) "मध्यम माल वाहन "से हल्का मोटर वाहन या भारी माल वाहन के अलावा कोई भी माल गाड़ी अभिप्रेत है; (24) "मध्यम यात्री मोटर वाहन "से कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन, या मोटर साइकिल, अमान्य गाड़ी, हल्की मोटर वाहन या भारी यात्री मोटर वाहन के अलावा शैक्षणिक संस्थान की बस अभिप्रेत है।

(25) “मोटरकैब "से कोई भी मोटर वाहन अभिप्रेत है जिसका निर्माण या अनुकूलन किराए या पुरस्कार के लिए चालक को छोड़कर छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं किया गया है।

(26) “मोटर कार "से परिवहन वाहन, सर्वव्यापी बस, रोड-रोलर, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल या अमान्य गाड़ी के अलावा कोई भी मोटर वाहन अभिप्रेत है।

(27) “मोटर साइकिल "से दो पहियों वाला मोटर वाहन अभिप्रेत है, जिसमें मोटर वाहन से जुड़ी कोई भी अलग करने योग्य साइड-कार जिसमें एक अतिरिक्त पहिया हो;

(28) “मोटर वाहन "या" वाहन "का अर्थ है सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित कोई भी यांत्रिक रूप से संचालित वाहन, चाहे प्रणोदन की शक्ति किसी बाहरी 630 से उसमें प्रेषित की गई हो।

2017(1)

या आंतरिक स्रोत और इसमें एक चेसिस शामिल है जिसमें एक शरीर संलग्न नहीं किया गया है और एक ट्रेलर शामिल है; लेकिन इसमें एक निश्चित रेल पर चलने वाला वाहन या केवल एक कारखाने में या किसी अन्य संलग्न परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित एक विशेष प्रकार का वाहन या पच्चीस घन सेंटीमीटर से अधिक की इंजन क्षमता वाले चार पहियों से कम वाला वाहन शामिल नहीं है।

(29) “(30) "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक, और किसी मोटर वाहन के संबंध में जो किराया-खरीद, समझौते \*, या पट्टे के समझौते या परिकल्पना के समझौते का विषय है, उस समझौते के तहत वाहन का कब्जा रखने वाला व्यक्ति; (33) "निजी सेवा वाहन" से ऐसा मोटर वाहन अभिप्रेत है जिसका निर्माण या अनुकूलन चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए किया गया है और जिसका उपयोग सामान्य रूप से ऐसे वाहन के मालिक द्वारा या उसकी ओर से व्यक्तियों को ले जाने के उद्देश्य से, या उनके व्यापार या व्यवसाय के संबंध में किया जाता है।

(35) “"लोक सेवा वाहन" से कोई भी मोटर वाहन अभिप्रेत है जिसका उपयोग किराए या पुरस्कार के लिए यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है या अनुकूलित किया जाता है, और इसमें एक मैक्सिकैब, एक मोटरकैब, अनुबंध गाड़ी और मंच गाड़ी शामिल हैं;

(47) “परिवहन वाहन "का अर्थ है एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल गाड़ी, एक शैक्षणिक संस्थान बस या एक निजी सेवा वाहन;

## “मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के तहत अधिसूचनाएं

(केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं)

### 1. मोटर वाहनों के प्रकारों का विनिर्देश

नहीं। S.O.1248 (E), दिनांक 5.11.2004।— अभ्यास में

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियां और पूर्ववर्ती भूतल परिवहन मंत्रालय भारत का संघ सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में।

दिनांक 19 जून, 1992, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 और 2 में उल्लिखित मोटर वाहनों के प्रकारों को निर्दिष्ट करती है:-

तालिका 632

परिवहन वाहन (1)	गैर-परिवहन वाहन (2)
(i) माल ले जाने के लिए साइड कार के साथ मोटर साइकिल।	(i) व्यक्तिगत उपयोग के लिए साइड कार के साथ या उसके बिना मोटर साइकिल।
((ii) माल ले जाने के लिए ट्रेलर के साथ मोटर साइकिल।	(ii) मोपेड और मोटर चालित साइकिल (इंजन क्षमता 25 सीसी से अधिक)।
(iii) एक यात्री को पीछे ले जाने के लिए किराए पर मोटर साइकिल और माल या किराए पर यात्रियों के लिए मोटर चालित साइकिल-रिक्शा।	(iii) अमान्य गाड़ी। (iv) व्यक्तिगत उपयोग के लिए तीन पहियों वाले वाहन। ((v) मोटर गाड़ी। (vi) फोर्क लिफ्ट। (vii) रिग, जनरेटर,
((iv) लग्जरी कैब। (v)	

यात्री/माल के परिवहन के लिए तिपहिया वाहन। (vi) माल वाहक ट्रक या टैंकर या डाक वाहक (एन 1-एन 3 श्रेणी)। (vii) सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने वाले पावर टिलर और ट्रैक्टर। (viii) मोबाइल क्लिनिक या एक्स-रे वैन या लाइब्रेरी वैन। (ix) मोबाइल कार्यशालाएँ। (x) मोबाइल कैंटीन। (xi) निजी सेवा वाहन। (xi) (xii) लोक सेवा वाहन (xii)	कंप्रेसर जैसे उपकरणों से लैस वाहन या ट्रेलर। (viii) क्रेन से चलने वाला वाहन। (ix) कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर। (x) निजी सेवा वाहन, जो किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है और यदि घोषित किया गया है कि उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। निजी उपयोग के लिए कैंपर वैन या ट्रेलर। टो ट्रक, ब्रेकडाउन
--	--

जैसे मैक्सी कैब, मोटर कैब, स्टेज कैरिज और पर्यटक वाहनों सहित अनुबंध कैरिज। (xiii) शिक्षा संस्थान की बसें। (xiv) एम्बुलेंस। (xv) पशु एम्बुलेंस। (xvi) कैंपर वैन या ट्रेलर। (xvii) कैश वैन। (xviii) फायर टेंडर, स्रोर्क सीढियाँ, सहायक ट्रेलर और अग्निशमन वाहन। (xix) स्पष्टीकृत वाहन। (xx) सुनाई देता है। (xxi) ऑम्निबस	एक पुनर्प्राप्ति वाहन चलाएँ। (xiii) केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व वाले मीनार वैगन और पेड़ काटने वाले वाहन। (xiv) नियम 2 (सीए) में परिभाषित निर्माण उपकरण वाहन।
--	--



(7) खंड 2 की पूर्व-उल्लिखित उप-खंडों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के बीच अंतर पर विचार करता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जिन दो अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है, वे मोटर वाहन और मालिक हैं। खंड 2 (28) मोटर वाहन को सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित यांत्रिक रूप से संचालित वाहन के रूप में परिभाषित करती है, चाहे प्रणोदन की शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित हो, लेकिन इसमें 25 घन सेंटीमीटर से कम की इंजन क्षमता वाले वाहन शामिल नहीं हैं। उप-धारा (28) के अलावा उप-धारा 2 (21) से (29) विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों को परिभाषित करती है। इन उपखंडों में से प्रत्येक एक विशेष प्रकार के मोटर वाहन को परिभाषित करता है। हालांकि, जहां तक मालिक का संबंध है, खंड 2 (30) मालिक के प्रकार को निर्दिष्ट नहीं करती है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति मालिक हो सकता है। इसलिए हम उचित रूप से एक कंपनी जैसे न्यायिक व्यक्ति को मालिक मान सकते हैं। उप-धारा 2 (33) और 2 (35) मोटर वाहनों के दो वर्गों या श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है अर्थात् निजी सेवा वाहन और सार्वजनिक सेवा वाहन। एक निजी सेवा वाहन को एक मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार और ए. एन. ओ. टी. आर. बनाम भारत का संघ और अन्य के अलावा व्यापार या व्यवसाय के संबंध में चालक के अलावा छह से अधिक व्यक्ति होते हैं।

633

अन्य (जे. अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल)

किराया या इनाम के लिए। सार्वजनिक सेवा वाहन को एक ऐसे वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग किराए या पुरस्कार के लिए किया जाता है। उप-खंड 2 (47) परिवहन वाहन को परिभाषित करती है जिसमें चार वर्ग शामिल हैं जैसे (ए) सार्वजनिक सेवा वाहन (बी) माल गाड़ी (सी) एक शैक्षणिक संस्थान बस और (डी) एक निजी सेवा वाहन। इसलिए, उप-धारा 2 (47) में परिवहन वाहनों के केवल चार वर्गों को परिभाषित किया गया है। इस प्रकार अन्य सभी श्रेणियों को गैर-परिवहन वाहनों के रूप में माना जाना चाहिए।

(8) निजी उपयोग के लिए किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले वाहनों और किराए या पुरस्कार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों का वर्गीकरण मान्य है। विशुद्ध रूप से निजी उपयोग और वाहनों के वाणिज्यिक उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इसी तरह वाहन के विशुद्ध रूप से निजी उपयोग और व्यापार या व्यवसाय के संबंध में व्यक्तियों को ले जाने के लिए वाहनों के उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इस तरह के वर्गीकरण में कुछ भी अतार्किक या अवैध नहीं लगता है।

(9) नतीजतन इस बात में कोई संदेह नहीं प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के वाहन जो व्यापार और व्यवसाय के संबंध में कर्मचारियों को ले जा रहे हैं, वे उप-खंड 2 (33) में परिभाषित निजी सेवा वाहन की श्रेणी में आते हैं। एक बार जब याचिकाकर्ताओं के वाहन निजी सेवा वाहन की श्रेणी में आते हैं, तो यह स्वयंसिद्ध है कि यह परिवहन वाहन की श्रेणी में आएगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं

के वाहनों को दिनांकित अधिसूचना की प्रविष्टि (xi) में वर्गीकृत किया जाना सही है और हम इसे किसी भी तरह से मनमाना या अवैध नहीं पाते हैं।

(10) जहां तक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को गैर-परिवहन वाहन के रूप में खंडीकृत करने का संबंध है, उप-धारा 2 (47) में खंडीकृत वाहनों की उपर्युक्त चार श्रेणियों से यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहन धारा 2 (47) में खंडीकृत वाहनों के इन चार खंडों में नहीं आते हैं। इसलिए, हम याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ता के वाहनों को गैर-परिवहन वाहनों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जैसा कि व्यक्तिगत मालिकों के स्वामित्व वाले वाहनों के मामले में किया जाता है। याचिकाकर्ता के वाहनों का उपयोग कर्मचारियों को उनके आवास से मिल तक ले जाने के लिए किया जा रहा है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता की कंपनी व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्यम चला रही है। जिन कर्मचारियों को इन वाहनों में ले जाया जा रहा है, उनका काम सीधे कंपनी के वाणिज्यिक उद्देश्य से संबंधित है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहन पूरी तरह से अलग आधार पर होंगे। वे कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं जैसा कि याचिकाकर्ता कंपनी के मामले में अपने कर्मचारियों को मिल तक पहुँचाते समय किया जा रहा है। इस प्रकार, हम कोई मनमानेपन या 634 नहीं पाते हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

उन व्यक्तियों के मामले में, जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, दिनांकित अधिसूचना 05.11.2004 में अंकित भेद में भेदभाव।

(11) हम अब यात्री कर का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ता के दायित्व का विज्ञापन करते हैं जो तत्काल याचिका में भी आक्षेपित है। पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 के प्रासंगिक प्रावधान इसके बाद दिए गए हैं:-

### “ परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो, -

(क) "व्यवसाय" से मोटर वाहनों द्वारा यात्रियों और वस्तुओं को ले जाने का व्यवसाय अभिप्रेत है;

(ग) "किराया" में सीजन टिकट के लिए या अनुबंध गाड़ी के किराए के संबंध में देय राशि शामिल है;

(ड) "स्वामी" से हरियाणा राज्य के क्षेत्र द्वारा या उसके माध्यम से यात्रियों या वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन का मालिक अभिप्रेत है और इसद्वारा शामिल हैं -

((i) ऐसे वाहन के संबंध में परमिट धारक,

((ii) कोई भी व्यक्ति जो उस समय ऐसे वाहन का प्रभारी है,

((ग) ऐसे स्वामी के व्यवसाय के स्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति,

((iv) सरकार या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत गठित निगम;

(च) "यात्री" से निजी और सार्वजनिक वाहक के अलावा मोटर वाहन में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, लेकिन इसमें वाहन के संबंध में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने वाले वाहन के चालक या चालक या वाहन के मालिक का कर्मचारी शामिल नहीं होगा।

(छ) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(छ) "निजी वाहक" से माल की ढुलाई के लिए उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक वाहक के अलावा कोई अन्य माल भारत का संघ है जो मालिक की संपत्ति है या जिसकी ढुलाई मालिक के व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है जो डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार और अन्य का व्यवसाय नहीं है।

635

अन्य (जे. अनुपिंदर सिंह प्रेवाल)

परिवहन या निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहन प्रदान करना:—

(क) परिवहन प्रदान करने के व्यापार या व्यवसाय के अलावा उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यापार या व्यवसाय के दौरान बेचे गए, उपयोग किए गए या किराए पर लिए गए माल के मालिक द्वारा या उसकी ओर से वितरण या संग्रह;

(बी) माल के मालिक द्वारा या उसकी ओर से डिलीवरी या संग्रह जो उसके द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय के दौरान एक प्रक्रिया या उपचार के अधीन रहा है या जिसके अधीन होना है; या

(ग) परिवहन वाहन में ऐसे माल के निर्माता या एजेंट या डीलर द्वारा माल की ढुलाई, जब वाहन का उपयोग प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो;

(जी. जी. जी.) "सार्वजनिक वाहक" का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी समय और किसी सार्वजनिक स्थान पर किराए या पुरस्कार के लिए माल, या माल के किसी भी वर्ग के परिवहन के लिए परिवहन या उपक्रम, चाहे वह किसी अनुबंध या समझौते की शर्तों के अनुसरण में हो या अन्यथा;

(i) "मोटर वाहन" का अर्थ है एक सार्वजनिक सेवा वाहन और इसमें सार्वजनिक वाहक, निजी वाहक या एक ट्रेलर शामिल है जब ऐसे किसी वाहन से जुड़ा होता है और सरकार के अलावा किसी अन्य नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वव्यापी बस;

(जे) इस अधिनियम में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) में सौंपा गया है।

### **कर का शुल्क।**

3. (1) राज्य सरकार पर ऐसी दर से कर लगाया जाएगा, प्रभारित किया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा जो -

((i) निजी वाहक के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले सभी यात्रियों और सामानों पर, जैसा भी मामला हो, किराया या माल ढुलाई; और

(ii) राज्य 636 के रूप में, एक निजी वाहक द्वारा ले जाए जाने वाले सभी सामानों पर [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59)] के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक वाहकों के लिए निर्धारित माल ढुलाई दर के आधार पर गणना की गई माल ढुलाई।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

सरकार, अधिसूचना द्वारा, दो पैसे या उससे कम को नजरअंदाज करके और दो पैसे से अधिक को पांच पैसे के रूप में गिनकर कर की राशि की गणना पांच पैसे के निकटतम गुणक में करने का निर्देश दे सकती है:

बशर्ते कि अनुबंधित डिब्बों, सार्वजनिक वाहकों और निजी वाहकों के मामले में, राज्य सरकार यात्रियों और वस्तुओं पर क्रमशः प्रभार्य कर के बदले में निर्धारित तरीके से एकमुश्त राशि प्रतिग्रहण करना कर सकती है:

बशर्ते कि स्टेज कैरिज के मामले में, राज्य सरकार यात्रियों और वस्तुओं पर प्रभार्य कर के बदले में एकमुश्त राशि को उस तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन प्रतिग्रहण करना कर सकती है जो निर्धारित की जाए:

आगे कहा गया है कि -

(क) भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात किए जाने वाले खनिजों और खनिज अयस्कों सहित वस्तुओं पर ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे वह एक लेनदेन द्वारा हो या लेनदेन की एक श्रृंखला द्वारा;

(ख) भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर ले जाए जाने वाले खनिजों और खनिज अयस्कों के संबंध में, ऐसा कर माल ढुलाई के मूल्य के बीसवें हिस्से की दर से लगाया जाएगा, लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा;

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों या उप-पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों द्वारा ले जाए जाने वाले सभी यात्रियों और वस्तुओं पर कर की दर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की गई है, किराया या माल ढुलाई के मूल्य का छठा हिस्सा होगी।

स्पष्टीकरण।— जब यात्रियों और वस्तुओं को एक निजी वाहक के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन द्वारा ले जाया जाता है, और कोई किराया या मालभाड़ा नहीं लिया जाता है या केवल सांकेतिक या इकबालिया किराया या मालभाड़ा लिया जाता है, तो कर लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा जैसे कि ऐसे यात्रियों और वस्तुओं को मार्ग पर प्रचलित सामान्य दर पर या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर ले जाया जाता है, जो भी अधिक हो।”

(12) खंड 2 (i) एक मोटर वाहन को एक निजी वाहक के साथ-साथ सरकार के अलावा किसी अन्य नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वव्यापी बस को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है। खंड 2 (जे) में, यह कहा गया है कि अधिनियम में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ डी. सी. एम. टेक्सटाइल्स, हिसार और ए. एन. ओ. टी. आर. बनाम भारत का संघ और

637

अन्य (जे. अनुपिंदर सिंह प्रेवाल)

इसका वही अर्थ है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 2 (29) में सर्वव्यापी शब्द को एक मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता के वाहन जो अपने कर्मचारियों को ले जा रहे हैं, उन्हें पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 में परिभाषित मोटर वाहन की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

(13) याचिकाकर्ता का मामला है कि परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के लिए कराधान का एक अलग तरीका/दर है और इसके वाहनों पर अधिक दरों पर यात्री कर लगाया गया है। हालाँकि याचिका में विवरण नहीं दिए गए हैं, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तियों के स्वामित्व

वाले वाहनों पर याचिकाकर्ता कंपनी के वाहनों की तुलना में कम दरों पर कर लगाया जाएगा। पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 की खंड 2 (च) में 'यात्री' की परिभाषा में मोटर वाहन में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है, लेकिन वाहन के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यात्रा करने वाले मालिक के चालक, कंडक्टर या कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया है।

(14) हम याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के साथ पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 के तहत यात्रियों के रूप में व्यवहार करने और कंपनी को यात्री कर के अधीन करने में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। जिन कर्मचारियों को उनके आवास से मिल तक ले जाया जा रहा है, उन यात्रियों को यात्रियों की परिभाषा के दायरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। परिभाषा में केवल वाहन के संबंध में कर्तव्यों के निर्वहन में चालक, कंडक्टर या एक कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया है जो अच्छी तरह से स्वच्छ हो सकता है आदि लेकिन कंपनी के अधिकारी जिनका वाहन से कोई संबंध नहीं है। खंड 3 (1) स्वयं याचिकाकर्ताओं के वाहनों को इसके दायरे में शामिल करती है। याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों को खंड 2 (च) में शामिल किया गया है। इसलिए हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकते हैं कि उसके कर्मचारी जो उसके वाहनों से मिल तक यात्रा करते हैं, वे यात्री नहीं हैं।

(15) इसके अलावा, खंड 3 को नंगे पढ़ने से संकेत मिलता है कि कर की गणना किराए के प्रतिशत के रूप में की जानी है। किराया खंड 2 (सी) में परिभाषित किया गया है जिसमें एक सीजन टिकट के लिए या गाड़ी के अनुबंध के किराए के संबंध में देय राशि शामिल है। खंड 3 (1) के स्पष्टीकरण में यह निर्धारित किया गया है कि भले ही यात्रियों को मोटर वाहन द्वारा ले जाया जाता है और कोई किराया नहीं लिया जाता है, कर लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा जैसे कि ऐसे यात्रियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य दर पर ले जाया जाता है। इसलिए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी अपने कर्मचारियों से शुल्क नहीं लेती है, इसका मतलब यह नहीं है कि किराया की गणना नहीं की जा सकती है। इसकी गणना 638 के अनुसार की जानी है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

खंड 3 (1) का स्पष्टीकरण। निजी वाहक के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों पर किराया लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कर्मचारी यात्री हैं। याचिकाकर्ता कंपनी के वाहन मोटर वाहन हैं न कि निजी वाहक जो सामान आदि ले जाते हैं। इसलिए, वे पूरी तरह से खंड 2 (i) में आते हैं।

(16) इन कारणों से हम याचिकाकर्ताओं के वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में वर्गीकृत करने और उन पर यात्री कर लगाने में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

(17) परिणामस्वरूप याचिका खारिज हो जाती है।

पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम,

हरियाणा